भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–01 अप्रैल, 2017

छत्तीसगढ़ सरकार के लोक सुराज अभियान का बहिष्कार करने का आह्वान!

छत्तीसगढ़ की ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार हर साल की तरह इस साल भी 3 अप्रैल से 20 मई तक लोक सुराज अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है जोकि बहुत बड़ा ढोंग है, जनता के साथ धोखा है, जनता को भटकाने व दिग्भ्रमित करने की नौटंकी है जिसका बहिष्कार करने हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करती है.

छत्तीसगढ़ में सुशासन का सुराज नहीं बल्कि शोषण–दमन का कुशासन जारी है. छत्तीसगढ़ की धरती भाजपा के शासन में देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानापरस्त जन विरोधी नीतियों खासकर संसाधनों की सस्ती लूट व सरकारी सशस्त्र बलों के पाशविक व बर्बर दमन से धधक रही है. लोक सुराज अभियान इसी सच्चाई को झुठलाने की छत्तीसगढ़ सरकार की साजिशपूर्ण योजना है.

भाजपा के सुराज में अन्नदाता किसानों की आत्महत्याएं लगातार जारी हैं. पूरे देश में पिछले कई सालों से इस मामले में राज्य पांचवें स्थान पर बरकरार है. 2016 में कुल 720 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की. धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए व बोनस 300 रुपए प्रति क्विंटल देने का चुनावी वादा कोरी बकवास साबित हुई. श्रम कानूनों को पूंजीपतियों के हित में शिथिल बनाने की कवायद जारी है. देशीय पूंजीपतियों को सस्ते दाम में कच्चा माल–लौह अयस्क एवं बिजली उपलब्ध न कराने के चलते राज्य के करीबन 150 मिनी स्टील प्लांट एवं स्पंज आइरन उद्योग बंद पड़े हैं जिसके कारण 50 हजार से भी ज्यादा मजदूर रोजी–रोटी से वंचित हो गए हैं.

गरीबी रेखा से नीचे के लाखों परिवारों के राशन काड्र्स स्क्रूटिनी के नाम पर जब्त करके बाद में रद्द कर दिए गए हैं. 35 किलो चावल प्रति राशन कार्ड जोकि एक परिवार के लिए अपर्याप्त थे, की जगह अब सिर्फ प्रति व्यक्ति 7 किलो कर दिया गया है. यह गरीबों के साथ खिलवाड़ ही है. राज्य में भूख से होने वाली मौतों का सिलसिला थमा नहीं है. बेरोजगारी का आलम यह है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस, अर्ध–सैनिक व सैन्य बलों में छोड़ अन्य किसी भी सरकारी विभाग में कोई भर्ती नहीं हो रही है. जबकि दसियों हजार पद रिक्त हैं. कहीं कोई भर्ती होती भी है जैसा कि शिक्षाकर्मी नियुक्ति, तो पूरी तरह अस्थायी. आउटसोर्सिंग के नाम पर राज्य के बेरोजगार युवक–युवतियों को छला जा रहा है. शिक्षा का निजीकरण व भगवाकरण बेरोकटोक जारी है. युक्तियुक्तकरण के नाम पर राज्य में 3 हजार शालाओं को बंद कर दिया गया है जिससे राज्य के आदिवासी, दलित एवं मुसलमान बच्चे खासकर बालिका शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है. मुख्य मंत्री रमण सिंह का नारा – 'बच्चों, पढ़ो–बढ़ो' सिर्फ जुमला ही रह गया है. स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की कोशिशें तेज कर दिए गए हैं. रमण के सुराज में आपराधिक लापरवाही व साजिशपूर्ण योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य शिविरों में गरीब लोगों की आंखों की रोशनी छीनी गयी, महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए, नसबंदी कांड में महिलाओं की जानें गई एवं अन्य शिविरों में महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ जानलेवा खिलवाड़ जारी है. आवासहीनता बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है. हालांकि शुद्ध पेयजल का घोर अभाव है लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने खुद ही शराब बनाकर, दुकानें खोलकर लोगों को शराब पिलाने का कार्यभार अपने कंधों पर उठा लिया है.

सिंचाई के प्रति राज्य सरकार की घोर लापरवाही के चलते कई पुरानी सिंचाई योजनाएं लंबित पड़ी हैं तो नई योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट मंजूर नहीं किया जा रहा है. इससे किसानों को वर्षा पर निर्भर करने मजबूर होना पड़ रहा है. अतिरिक्त बिजली का दंभ भरने के बावजूद आज भी सैकड़ों गांव विद्युत विहीन हैं. बिजली कटौती जारी

है. लो वोल्टेज की समस्या से किसान जूझ रहे हैं. बिजली की दरें आसमान छू रही हैं. आजीविका की तलाश में साल–दर–साल बढ़ता पलायन जिससे छत्तीसगढ़िया जनता निर्मम शोषण, गाली–गलौच, मार–पीट, लूट, महिलाओं के यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी का शिकार हो रही है, राज्य की भाजपा सरकार के सुराज की पोल खोल रहा है.

नेताओं जिनमें स्वयं मुख्य मत्री का संसद बेटा भी शामिल है व नौकरशाहों का भ्रष्टाचार एवं घोटालें जग जाहिर है. मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से लेकर शिक्षाकर्मी सहित तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर हर साल हड़तालें, अनशन, आन्दोलन जारी हैं.

राज्यसत्ता के प्रत्यक्ष भागीदारी व संरक्षण में 'घर वापसी' के नाम पर आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों व ईसाइयों का जबरन हिन्दूकरण, गोमांस पर पाबंदी लगाकर आदिवासियों, दलितों व मुसलमानों के खान–पान की आदतों सहित उनकी संस्कृति व जीवनशैली पर पाशविक हमलें, गोरक्षा के नाम पर इन तबकों के लोगों पर जानलेवा हमलें, पिटाई, उनकी गिरफ्तारी, जेल व सजाएं बेरोकटोक जारी हैं. आदिवासी बहुल इलाकों में इनका खतरनाक ढंग से विस्तार हो रहा है.

आदिवासियों व किसानों को विस्थापित करने की ढेरों खनन परियोजनाओं, वृहद औद्योगिक परियोजनाओं, बहु उद्देश्यीय बांध परियोजनाओं से संबंधित एमओयू किए गए हैं और उन पर अमल के लिए इन परियोजनाओं के प्रस्तावित स्थलों के इर्द–गिर्द बड़े पैमाने पर पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों को तैनात करके नए कैंप व थानें खोल दिए गए हैं. विस्थापन विरोधी जन आन्दोलनों, प्रगतिशील–जनवादी व मानवाधिकार एवं सामाजिक आन्दोलनों सहित हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन के सफाए के मकसद से इन सशस्त्र बलों के सहारे हर दिन गांवों पर एवं जंगलों में गश्त के नाम पर हमलें करवाए जा रहे हैं. आदिवासी ग्रामीणों, छात्रों, नवजवानों, महिलाओं की फर्जी मुठभेडों में हत्याएं, झूठे आत्मसमर्पण, नरसंहार, सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार व हत्याएं, महिलाओं पर अकथनीय यौन उत्पीड़न, सामूहिक पिटाई, गृहदहन, झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में सड़ाना, बिना सबूत या झूठे सबूत के आधार पर लंबी व आजीवन कारावास की सजाएं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं, विपक्षी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर प्रतिक्रियावादी व प्रतिक्रांतिकारी संगठनों व गुण्डा गिरोहों जैसे सामाजिक एकता मंच, महिला एकता मंच, नक्सल पीड़ित संघ, अग्नि आदि द्वारा हमलें राज्य के बस्तर संभाग सहित राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद जिलों में रोजमर्रा की बात हो गयी हैं. एक वाक्य में कहा जाए तो राज्य की उत्पीड़ित जनता एवं जनपक्षधर लोगों पर नाजायज युद्ध–ऑपरेशन ग्रीन हंट के हमलों में अभूतपूर्व तेजी भाजपा राज की विशेषता बन गयी है.

जन विरोध के सामने झुककर केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बावजूद जनता के जल–जंगल–जमीन छीनने के लिए छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करना, सरकार की खिलाफत करने वालों को दबाने के लिए छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून बनाना भाजपा सरकार के जन विरोधी चरित्र का परिचायक हैं. समस्याओं से जूझने वाली जनता को सरकार लाठी, जेल व गोली परोस रही है. छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन की सच्चाई यही है. इसीलिए हमारी पार्टी जनता का आह्वान करती है कि वह सरकार के लोक सुराज अभियान का बहिष्कार करें एवं इस हेतु गांवों में आने वाले भाजपा नेताओं व नौकरशाहों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करें एवं जन समस्याओं के बारे में जवाब तलब करके आवश्यक सजा देवें. छत्तीसगढ़ की जनता के सामने समस्याओं का अंबार है जिनका समाधान लुटेरी सरकार नहीं करेगी. इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए सभी उत्पीड़ित जनता को एकताबद्ध होकर व्यापक, संगठित व जुझारु संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ने का हमारी पार्टी आह्वान करती है.

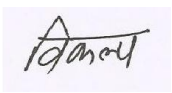

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)